

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)  
(RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2005/PN1/32

New Delhi, Dated 29.04.2009.

The GMs/FA&CAOs,  
All Indian Railways/Production Units.  
(As per mailing list)

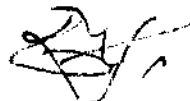
**Subject: Simplification of procedures outlined in sub Rule 4 of Rule 75(6) of Railway Services(Pension) Rules,1993 regarding Family Pension to Handicapped/Disabled son/daughter of Railway Servants/Pensioners – Reg.**

\*\*\*\*\*

A copy of Department of Pension and Pensioners' Welfare (DOP&PW)'s O.M. No. 1/16/08-P&PW(E) dated 9<sup>th</sup> March,2009 on the above mentioned subject, is enclosed for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on the Railways also.

2. Clause (iii) & (vi) and the explanation (d) thereunder below the proviso to Sub-rule 6 of Rule 54 of the CCS(Pension) Rules, 1972 correspond to clause (a) & (d) and explanation (4) of the proviso to Sub-rule 6 of Rule 75 of Railway Services(Pension) Rules,1993

3. Please acknowledge receipt.



(SUNIL BHARDWAJ)

Deputy Director Finance(Estt.)III,  
Railway Board.

DA: One.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (Railway Board)
13 APR 2009
के.रे.सं./C.R. No. ....
अनुमान क्रमही सं०
Section Dy. No. ....
वर्गीकरण/Class. ....

No.1/16/08-P&PW(E)  
Government of India  
Ministry of Personnel P.G. & Pension  
Department of Pension & Pensioners Welfare

Lok Nayak Bhawan  
Khan Market, New Delhi  
Dated the 9th March, 2009

### OFFICE MEMORANDUM

**Subject:** Simplification of procedures outlined in Rule 54(6) of CCS(Pension) Rules, 1972 regarding Family Pension to Handicapped/Disabled son/daughter of Government Servants/Pensioners – Reg.

The undersigned is directed to say that as per the existing provisions under clauses (iii) & (vi) and the explanation (d) thereunder below the proviso to Sub-rule 6 of Rule 54 of CCS(Pension) Rules, 1972, if the son or daughter of a Government servant is suffering from any disorder or disability of mind (including mentally retarded) or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to certain stipulations. Further, the family pension shall be paid to such son or daughter through the Guardian as if he or she were a minor except in the case of physically crippled son/daughter who has attained the age of majority. In the case of a mentally retarded son or daughter, the family pension shall be payable to a person nominated by the Government or the pensioner, as the case may be. It has been further provided that it shall be the duty of the Guardian or son or daughter to furnish a certificate to the Treasury/Bank, as the case may be, every month to the effect that – (i) he /she has not started earning his/her livelihood; and (ii) in case of daughter, that she has not yet married.

2. Representations have been received in this Department requesting for simplification of procedures concerning family pension to handicapped/disabled son/daughter of Government servants/pensioners, particularly with regard to **submission of a certificate to the Treasury/Bank, as the case may be, every month** by the guardian or son or daughter, to the effect (i) that he/she has not started earning his/her livelihood, and (ii) in case of daughter, that she has not yet married. These procedures are stated to be cumbersome and unreasonable thereby causing hardship to the concerned.

3. The matter has been examined in this Department in consultation with the Ministry of Finance(Department of Expenditure). Taking note of these concerns, and the difficulties being faced by those affected by the existing cumbersome procedures in this regard, it has accordingly been decided that in all such cases the Guardian or son or daughter, shall furnish a certificate to the Treasury/Bank, as the case may be, **every year**

instead of every month, as in the existing provisions, subject to the condition that in case of any eventuality taking place at any point of time during the year, the same shall be reported by the guardian or son or daughter, to the Bank/Treasury at the earliest possible.

4. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their U.O.No. 563/E.V/2008 dated 22.10.2008.

5. These orders, in so far as their applicability relates to the employees of the Indian Audit and Accounts Department, are being issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, vide their U.O. No.19-Audit (Rules)/26-2008 dated 6.3.2009.

  
(M.P.SINGH)  
DIRECTOR

To,

All Ministries, Departments of Government of India.

सं. 1/16/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

\* \* \*

लोकनायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.  
दिनांक : 9 मार्च, 2009

### कार्यालय जापन

**विषय :-** सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों के विकलांग/अशक्तता से ग्रस्त पुत्र/पुत्री को परिवार पेंशन के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54(6) में प्रक्रियाओं का सरल बनाया जाना ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 के उप-नियम 6 में परन्तुक के नीचे खण्ड (iii) और (iv) तथा इस पर स्पष्टीकरण(घ) के अंतर्गत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार यदि किसी सरकारी सेवक का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या अशक्तता (मस्तिष्क व्याघात सहित) से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग या अशक्तता से ग्रस्त है, जिससे वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बावजूद भी जीविका कमाने में असमर्थ हो गया है, ऐसे पुत्र या पुत्री को कतिपय निबन्धों के अधीन परिवार पेंशन आजीवन देय होगी । इसके अतिरिक्त, शारीरिक रूप से अपंग पुत्र/पुत्री, जिन्होंने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, के मामलों को छोड़कर यदि वह नाबालिग हो, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी । मस्तिष्क व्याघात से ग्रस्त पुत्र या पुत्री के मामले में, परिवार पेंशन सरकार या पेंशनभोगी, जैसी स्थिति हो, के द्वारा नामांकित व्यक्ति को देय होगी । इसके अतिरिक्त यह प्रावधान किया गया है कि संरक्षक या पुत्र या पुत्री का यह दायित्व होगा कि वह ट्रेजरी/बैंक, जैसी स्थिति हो, को प्रत्येक महीने इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि - (i) उसने जीविका कमाना शुरु नहीं किया है; और (ii) पुत्री के मामले में यह कि उसका अब तक विवाह नहीं हुआ है ।

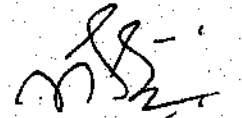
2. सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों के विकलांग/अशक्तता से ग्रस्त पुत्र/पुत्री को परिवार पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं, विशेष रूप से ट्रेजरी/बैंक, जैसी स्थिति हो, को इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि (i) उसने जीविका कमाना शुरु नहीं किया है; और (ii) पुत्री के

मामले में यह कि उसका अब तक विवाह नहीं हुआ है, प्रत्येक महीने प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस विभाग को अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्रक्रियाओं का दुर्वहनीय और असंगत होने के कारण संबंधितों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

3. इस विभाग में मामले पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच-पड़ताल की गई है। इस संबंध में मौजूदा दुर्वहनीय प्रक्रियाओं से प्रभावितों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें और इन संबंधितों को ध्यान में रखते हुए, तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में संरक्षक या पुत्र या पुत्री ट्रेजरी/बैंक, जैसी स्थिति हो, को मौजूदा प्रावधानों में प्रत्येक महीने के स्थान पर प्रत्येक वर्ष एक प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन प्रस्तुत करेंगे कि वर्ष के दौरान किसी समय होने वाली घटना के मामले में संरक्षक या पुत्र या पुत्री, बैंक/ट्रेजरी को यथाशीघ्र सूचित कर देंगे।

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की यू.ओ.सं. 563/ई.वी./2008 दिनांक 22.10.2008 द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

5. इन आदेशों को भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के संबंध में लागू किए जाने के संबंध में ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की यू.ओ.सं. 19-लेखा-परीक्षा(नियमावली)/26-2008 दिनांक 6.3.2009 द्वारा उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।



(एम. पी. सिंह)

निदेशक (पी.पी.)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग